action at their end. Their opinions were not asked for.

Statement

The procedure regarding appointment of Vice-Chancellors of the Aligarh, Banaras, Delhi and Visva-Bharati Universities is as follows :—

Aligarh Muslim University :

The Vice-Chancellor is appointed by the Visitor from among persons recommended by the Executive Council. If the Visitor does not approve of any of the persons so recommended, he may call for fresh recommendations from the Executive Council.

Banaras Hindu University :

The Vice-Chancellor is appointed by the Visitor on the recommendation of a Selection Committee constituted by the Visitor for the purpose. If the Visitor does not approve of such recommendation, he may call for one or more fresh recommendations.

Delhi University :

The Vice-Chancellor is appointed by the Visitor from a panel of not less than three persons selected by a committee consisting of three persons, two of whom nominated by the Executive Council and one person nominated by the Visitor. One of the three persons is appointed by the Visitor as the Chairman of the Committee. If the Visitor does not approve of any of the persons so recommended, he may call for fresh recommendations.

Visva-Bharati, Santiniketan :

The Karma-Samiti (Executive Council) forwards a panel of three names to the Samsad (Court) with their recommendations in order of preference. If the Samsad (Court) by a simple majority accepts the first name on the panel forwarded by the Karma-Samiti (Executive Council), the Paridarsaka (Visitor) confirms the appointment. If, however, the first name on the panel is not acceptable to the Samsad (Court), the panel is forwarded to the Paridarsaka (Visitor) with the recommendation of the Karma-Samiti (Executive Council) and the Samsad (Court) and the appointment is made by the Paridarsaka (Visitor) from the panel of names.

Recommendation of Administerative Reforms Commission Regarding Pay and Allowances of I. P S. Officers

807. SHRI MANGALATHUMADAM : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Administrative Reforms Commission has recommended to enhance the pay and allowances of the I. P. S. officers ;

(b) if so, the reaction of Government to these recommendations ; and

(c) whether his Ministry has written to the Finance Ministry/Pay Commission to consider the question ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

सचिवालय में तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

808. श्री राम सेवक यादव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सुझाव दिया है कि सचिवालय में अधिकांश पदों पर तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना चाहिए ;

(ख) क्या इसी प्रकार का एक सुझाव चौथी योजना के प्रारूप में भी दिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस समय ऐसे पदों पर भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी कार्य कर रहे हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यदि प्रशासनिक सुधार आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया तो अनेक भारतीय प्रशासन सेवा के कई अधिकारी बेरोजगार हो जायेंगे ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की और भर्ती बन्द करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । किन्तु प्रशासनिक सुधार आयोग ने कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सचिवालय में कार्यशील क्षेत्र में सभी पदों पर तद्नूरूप कार्यशील सेवा के सदस्य अथवा ऐसे कार्यशील अधिकारी जो सेवा के संवर्ग में न हों, नियुक्त किये जाने चाहिए और जो पद एक विशेष कार्यशील क्षेत्र में न आते हों वे पद श्रेणी-1 के अधिकारियों के लिए खुले होने चाहिए ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । योजना के प्रारूप में यह सुझाव दिया गया है कि विशेषज्ञों, तकनीकियों और दक्ष व्यक्तियों को प्रशासन के सभी स्तरों पर एक उत्तरदायित्व रीति में योगदान देने के लिए समर्थ बनाना होगा ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । वर्तमान में सचिवालय में ऐसे पदों पर अखिल भारतीय तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न मंत्रालयों में अधिकारी, इंजीनियर, तकनीशियन और उनमें विशेषज्ञ

809. श्री राम सेवक यादव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण, आवास और नगरीय विकास, संचार, सिंचाई तथा विद्युत, इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग, खान तथा धातु और औद्योगिक विकास मंत्रालयों में अवर सचिव तथा उससे उच्च पदों पर नियुक्त अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और विशेषज्ञों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या जिन पदों पर चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के अनुच्छेद 6-12 और 6-13 के अनुसार इन्जीनियरों और विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना था, उन्हें तदनुसार इस प्रकार के व्यक्तियों से भरा गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इन्जीनियरों में बेरोजगारी दूर करने के लिए चौथी योजना में शामिल सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 112

(ख) 4

(ग) और (घ). सचिवालय के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों और पदधारक के लिए आवश्यक योग्यताओं तथा अनुभव को ध्यान में रखकर की जाती हैं। सचिवालय के पदों को भरते समय योजना में निहित सिफारिशों को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाता है ।

Earning of Profits by Ashoka Hotels and other Government Owned Hotels

811. DR. RAM SUBHAG SINGH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the Ashoka Hotel and other Government owned hotels have made any progress in profit making ;

(b) which of the hotels are still running on loss ; and

(c) the steps being taken to see that these hotels do not incur losses ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b). The Ashoka Hotel has been making profits since 1960 and expects to continue doing so for 1969-70 also.

The Janpath Group of Hotels consists of the Janpath, Lodhi and Ranjit. While the Janpath Unit has been making a profit, the group as a whole has suffered a loss. For the year 1969-70, however, the group expects to make a profit.